

देश की उपासना

(देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए)

वर्ष - 03

अंक - 48

जैनपुर, शनिवार, 05 अक्टूबर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

**मिर्जापुर में हुआ
भयानक हादसा,
10 मजदूरों की
हुई मौत**

मिर्जापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कछाव सीमा के पास शुक्रवार को एक ट्रक और ड्रैग्वर्टर के बीच हुई टक्कर में दस मजदूरों की मौत हो गई, जबकि उन्होंने जान अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना जीटी रोड पर मिर्जापुर कछाव सीमा पर उस समय हुई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने एक ड्रैग्वर्टर को पीछे से टक्कर मार दी, जो 13 लोगों को लेकर भारतीय जिले से बनारस की ओर जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन घायलों को इलाज के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचय) अस्पताल में भेजा। पुलिस ने बताया कि 13 लोग भारतीय में मजदूरी करते थे और अपने गांव लौट रहे थे। दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। रात की बजे एक बजे सूचना मिली कि मिर्जापुर कछाव बॉर्डर पर जीटी रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें भारतीय जिले से बनारस की ओर जा रहे 13 लोगों से भरे ड्रैग्वर्टर को पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी है।

**ऐतिहासिक
संरचनाओं को
नुकसान
पहुंचाया तो होगी
2 साल की जेल**

महाराष्ट्र, एजेंसी। महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से इस फैसले की लिस्ट शेयर की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रतावना परित किया है। पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने राज्य में गैर-कृषि कर्मों को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। प्राचीन और ऐतिहासिक मराठों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश, एजेंसी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृहराज्य हिमाचल प्रदेश के दोरे पर हैं। इस

क्लाउड-वायांटम कंप्यूटिंग इत्यादि पर कपड़ी को तकनीकी उपलब्ध कराते हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा पांच वर्ष के लिए तैयार की गई यूपी जीसीसी नीति-2024 को जल्द ही कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। हब एंड स्पॉक मार्जल पर विकसित किए जाने वाले जीसीसी के चार घटक होंगे, जिसमें ग्लोबल हब, सेटेलाइट ऑफिस, आउटसोर्सिंग व कलरस्टर और अॉफिस शामिल होंगे। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नीति के साथ ही पांच लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीसीसी के नीति से आईटी सेक्टर को और रपतार मिलेंगी।

विदेशभर में जीसीसी का तेजी से विस्तार होगा। आगरा, बरेली, गोरखपुर में गौतमभुद्धनगर जीसीसी के दो शैक्षणिक विद्यालय बनाए रखने के लिए नीति दर्शाया गया है। शर्मा के मुताबिक, 40 आईटी पार्क व 25 स्पेशल इकोनामी जॉन (एसईजे) में भी नीति के बढ़ाव देना चाहिए। जरिए निवेश व उपक्रम स्थापना को बढ़ाव दिया जाएगा। विश्व स्टरीय संसाधनों के साथ-साथ डिजिटल इंचेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जीसीसी के लिए न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। गौतमभुद्धनगर व गाजियाबाद में नीति के दर्शाया गया है। जीसीसी के नीति से आईटी सेक्टर को और रपतार मिलेंगी।

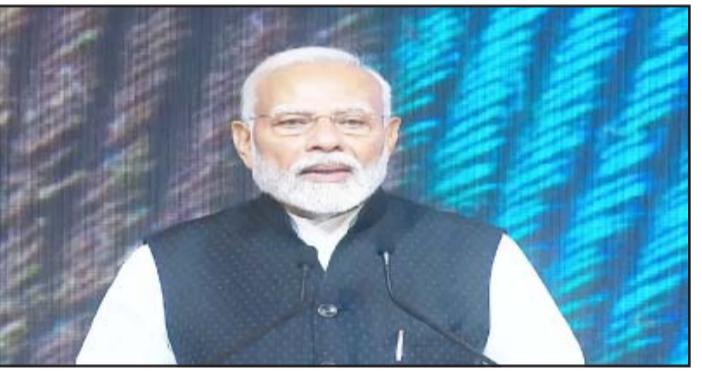
दर्जा देने का निर्णय किया है। ऐसे में आईटी कंपनियों को ओपोनिंग क्षेत्रों में आसानी से जमीनें के साथ ही बिजली पर भी छूट होंगी। जीसीसी की नीति से आईटी सेक्टर को और रपतार मिलेंगी। न्यूनतम 15 करोड़ का निवेश 500 लोगों को रोजगार देना होगा। जीसीसी के नीति के दर्शाया गया है। गौतमभुद्धनगर व गाजियाबाद में नीति के दर्शाया गया है। जीसीसी के नीति से आईटी सेक्टर को और रपतार मिलेंगी।

रोजगार उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी। एडवांसर्ड जीसीसी के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये है। गौतमभुद्धनगर व गाजियाबाद में एडवांसर्ड जीसीसी खोलने के लिए 75 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। इनमें एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार देना होगा। जीसीसी के नीति के दर्शाया गया है। प्रस्तावित नीति के तहत जीसीसी की दो श्रेणियां होंगी। प्रदेश में लेवल-वन के जीसीसी स्थापित करने के लिए न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का निवेश बढ़ाव दिया जाएगा। गौतमभुद्धनगर व गाजियाबाद में नीति के दर्शाया गया है। जीसीसी के नीति से आईटी सेक्टर को और रपतार मिलेंगी। एडवांसर्ड यूपी में ही आवेदन करना होगा। बुदेलखंड व पूर्वांचल में जमीन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। तथा समय में जीसीसी स्थापित न होने की दशा में अनुदान पर सरकार 12 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। एडवांसर्ड यूपी में जीसीसी स्थापित करना होगा। जीसीसी के नीति के दर्शाया गया है। बुदेलखंड व पूर्वांचल में जमीन पर 50 प्रतिशत समिक्षा आवेदन किया जाएगा। लीज रेट, डाटा सेंटर, बैंडविथ, कलाउड सर्विस व विद्युत आदि पर भी 20 प्रतिशत की दर से समिक्षा दी जाएगी। अगर कोई निवेशक बुदेलखंड

यूपी बनेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का सुपर हब - योगी



भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था - पीएम मोदी



मामले में नंबर वन हैं। आज हम स्मार्टफोन डेटा खपत के मामले में नंबर वन हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक वार्ताविक समय लेनदेन का आधा हिस्सा भारत में होता है। भारत में विकास के साथ-साथ नीति के उनके पास बड़ी समाजिक समस्याएँ हैं, और मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा नीति है। उन्होंने कहा कि इस्सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तनश भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 साल में 250 मिलियन... यानि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि इस्सुधार सबसे बड़ा नीति है। उन्होंने कहा कि इस्सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तनश भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस्सुधार सभी भावनाएँ भारत की विकास गाथा का एक और उत्तरेखनीयी कारक है। अब, भारत में, विकास के साथ-साथ समावेशन भी होता है। परिणाम वरुण, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की वृद्धी आर्थिकीयों का विश्वास ही हमारी ताकत है। हम भारत की लाभ लेने के लिए आमत्रित किया है

संपादकीय

जलवायु परिवर्तन की समरस्या

जाने—माने बौद्ध विचारक थिए नहत हान ने जलवायु परिवर्तन की गहराती समस्या पर कहा था कि यदि हम उसी रास्ते पर चलते रहें, जिस पर इस समय चल रहे हैं तो निश्चित ही मनुष्य जाति का विनाश हमारे अनुमानों से पहले ही हो जाएगा। जो लोग जलवायु परिवर्तन की स्थिति को समझते हैं और तथ्यों से परिचित हैं, उन्हें इससे कोई असहमति नहीं सकती है। आश्चर्य तब होता है जब विश्व भर में सत्ता पर काबिज लोग भी वर्तमान रास्ते को बदलने की बात तो लगातार करते हैं, अनेक उपायों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई व्यावहारिक बदलाव नहीं हो पाता है। इसका सबसे निकटस्थ उदाहरण है दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह समस्या। प्रतिवर्ष वही वादे, वही न्यायालय के नाराजगी भरे निर्णय और उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा लगातार अपनी कर्मठता जाहिर करते देखना मात्र तक ही दिल्ली की नियति बन गई है। वैसे यह समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, देशवापी है, विश्ववापी है। करीब बीस वर्ष पहले एक ऐसी संभावना बनी थी, जिसमें भारत की नई पीढ़ी को पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता था, मगर वह राजनीति की भेंट चढ़ गया। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी को दिसंबर 2003 में निर्देश दिया था कि वह पर्यावरण शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने के लिए कक्षा एक से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम बनाए, जिसे संस्था ने मार्च 2004 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा। यह राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत संतोष की स्थिति थी कि सभी राज्य सरकारों ने उस पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। साथ ही अपने स्कूल शिक्षा की संरचना में आवश्यक परिवर्तन कर पर्यावरण शिक्षा को एक अलग स्वतंत्र विषय बनाने की बात कही। मई 2004 में केंद्र में नई सरकार आ गई। चूंकि उक्त निर्णय पूर्ववर्ती सरकार के प्रयास का परिणाम था अतः उसने उस निर्णय को लागू नहीं किया। नीति—निर्धारण स्तर पर जब भविष्यदृष्टि की कमी होती है, तब अनेक ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जिनका आधार शैक्षिक या अकादमिक न होकर कहीं न कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के सतत संघर्ष में छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि यदि 20 वर्ष से पहले पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य और स्वतंत्र विषय बना दिया जाता तो देश के प्रशासन में आज युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी कार्यरत होती, जिसके मन मस्तिष्क में पर्यावरण रक्षा के प्रति श्रद्धा पैदा हो चुकी होती। संभव है कि उनमें से कोई एक दिल्ली की समस्या को चुनौती मानकर इसका समाधान करने के लिए जी जान से जुट जाता और सफल होता। इंदौर और सूरत जैसे शहरों में जो सफलताएं स्वच्छता को लेकर मिलीं और सारे देश में इन शहरों की सराहना हुई, उसके पीछे भी कहीं न कहीं एक उत्साहित, अध्ययनशील और भविष्यदृष्टि वाला व्यक्तित्व उपस्थित था। सामान्यजन अब यह समझ चुके हैं कि उत्तरदायी व्यक्ति यदि निष्ठापूर्वक किसी समस्या का समाधान करना चाहे तो रास्ते निकाल सकते हैं और समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि उन्हें अपने परिवार और करियर के बजाय जनसेवा को जीवन का उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र कहता है कि जो चयनित जनप्रतिनिधि संवैधानिक पदों पर नियुक्त होंगे वे जनसेवा के कारण ही वहां पहुंचेंगे और इसके बाद वे पूर्णरूपेण अपना सर्वस्व उसी के लिए समर्पित कर देंगे। यही अपेक्षा तो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी जैसे मनीषियों ने स्वतंत्र भारत में नेतृत्व प्रदान करने वाले जन प्रतिनिधियों से की थी। दुख की बात है कि उनकी अपेक्षाओं को वर्तमान राजनीतिक और दलगत वैचारिक प्रतिबद्धताओं की आधी-अधूरी समझ के अंतर्गत पूरी तरह नकार दिया गया है। हर उस क्षेत्र में जहां जनसाधारण का जीवन प्रभावित होता है, निर्णय ले सकने वालों की स्वार्थपरकता व्यक्ति के लिए कष्टकर स्थितियां ही उत्पन्न करती हैं। जनहित की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं इसी कारण अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को ही लें तो अनेक सरकारी योजनाओं की घोषणा होने के बावजूद आज भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति सामान्य व्यक्ति के लिए सुविधाजनक नहीं बन पाई है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की हालत और चिंताजनक है। उनमें नियुक्त डाक्टर सप्ताह में एक या दो दिन ही जाते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी यह सब जानते हैं, मगर पता नहीं क्यों किसी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस नहीं करते। अंततः लोग इस स्थिति को अपरिवर्तनीय मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वर्ष 2013 में आई न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में 10 हजार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान केवल व्यापार कर रहे हैं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उनकी कोई रुचि नहीं है और वे डिग्री बेच रहे हैं। नई शिक्षा नीति—2020 में भी इस कथन को शामिल किया गया है और शिक्षक प्रशिक्षण में गहन सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। शिक्षा नीति में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति के शब्दों को दोहराया जाना यह स्पष्ट करता है कि डिग्री बेचने वाले संस्थान इस बीच अपना कार्य करते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थागत निष्क्रियता और अन्यमनस्कता का यह एक सटीक उदाहरण है। देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। स्पष्ट है सामान्य जन के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन तभी होगा, जब देश का प्रबुद्ध वर्ग अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए आगे आएगा और सरकारी तंत्र ईमानदारी, कर्मठता और सेवा भाव को प्राथमिकता देगा।

संयुक्त राष्ट्र में

शिवकांत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भविष्य शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा, शुद्धिनिया एक बवंडर में फंसी है। हम ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक समाधान चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था, शुद्धिनिया वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, हताश होने के बजाय हमें एक जुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को और सक्षम, प्रभावी और समावेशी बनाने की जरूरत है। इसीलिए हम सुरक्षा परिषद का सुधार और विद्यालयों का सार्वानन्द

हरियाणा में पिछड़ रही भाजपा अब आगे हुई



तरह बाहर हो चुकी होती। खट्टर से व्यक्तिगत रूप से लोगों की नाराजगी भाजपा को चुनावों में उसी तरह नुकसान पहुँचा सकती थी जैसे कि राजस्थान विधानसभा के 2018 के चुनावों में देखने को मिला था जब नारे लग रहे थे कि मोदी तुझसे बैरानहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हमसे बातचीत में भाजपा के भी कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने माना कि यदि खट्टर को हटाने का फैसला एक साल पहले लिया गया होता तो लोकसभा चुनावों में भी हम सारी सीटें जीत सकते थे। इसके अलावा, 15 दिनों पहले जब हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की कवरेज की शुरुआत की थी उस समय सब जगह कॉंप्रेस की हवा ही दिख रही थी लेकिन एक एक दिन बीतने के साथ यह हवा हमें धीमी पड़ती दिखी और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो कहा जा सकता है कि हवा किसी एक के पक्ष में नहीं है बल्कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरियाणा चुनाव के

दौरान मुझे दिल्ली नगर निगम का पिछला चुनाव इसलिए याद आ गया क्योंकि उसमें भाजपा का सूपड़ा साफ होने की भविष्यत्वाणी की गई थी लेकिन जब परिणाम आये तो पार्टी नजदीकी मुकाबले में आम आदमी पार्टी से सिर्फ कुछ सीटों से पिछड़ गई थी। हरियाणा चुनावों में भी जमीनी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखी। ऐसा लगता है कि भाजपा को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह चुनाव में कांग्रेस से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है तो उसने पिछले 10 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जनसभाएं कराई गयीं और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने 70 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं कीं। जवाब में भाजपा ने 150 सभाएं और रैलियां कर माहौल

को पूरी तरह बदल दिया। हरियाणा में कांग्रेस ने जमीन तक इस बात को पहुँचाने में सफलता हासिल कर ली थी कि शकंग्रेस आरही है, भाजपा जा रही है। भाजपा ने इस हवा की चाल को धीमा करने के लिए परिवारवाद को मुद्दा बनाया और भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिछले शासन की याद दिलाई जिससे माहौल बदलने लगा। भाजपा ने जनता के बीच इस धारणा को मजबूत किया कि अगर कांग्रेस आई तो निश्चयत रूप से हुड्डा को कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने भी बार-बार हुड्डा को ही कमान सौंपने के संकेत दिये जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होता दिखा क्योंकि हुड्डा को अपने पिछले कार्यकाल में सिर्फ रोहतक का सीएम माना जाता था और उन पर अपने आलाकमान के खुश रखने के लिए प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप भी हैं। कई क्षेत्रों के लोगों का मानना है कि हुड्डा ने सिर्फ रोहतक में काम किया जिससे वहां की जमीनों के

रेट ज्यादा हैं और उनके इलाके की जमीनों का रेट बहुत कम है। इसके अलावा भाजपा ने जिस एकजुटता और रणनीति के साथ हरियाणा में काम किया उससे पार्टी मुकाबले में तेजी से वापसी करती दिखी। रैलियों, सभाओं और डोर टू डोर हुए प्रचार के बाद मिल रहे फीडबैक से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसलिए 3 अक्टूबर शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थमने तक भाजपा के प्रदेश के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री जनता के बीच लगातार पहुंचकर भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाने की अपील करते दिखे। भाजपा की रैलियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले लगभग एक महीने में प्रमुख नेताओं की 150 से अधिक जनसभाएं हुईं। प्रैगानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा

खतरे में विश्व शांति

आदत्य
हात्यारा

ईजरायल का आर स लबनान हिंजबुल्ला के सरगना नसरुल्ला मार गिराए जाने के बाद ईरान जिस तरह उस पर मिसाइलें गिरीं, उसके बाद पश्चिम एशिया हालात बेकाबू होते दिख रहे। इसलिए और भी, क्योंकि जरायल ने दो टूक कहा है कि ईरान को मिसाइल हमले के नतीजे प्रभावित होंगे। ईजरायल केवल ईरान की हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। उसने लेबनान में हिंजबुल्ला सबक सिखाने के लिए अपनी नारं भेज दी हैं और वह सीरिया अपने शत्रुओं पर हमला करने साथ यमन में हाउती लड़ाकों भी निशाना बना रहा है। हमास, जबुल्ला और हाउती वे संगठन जिन्हें ईरान हर तरह का हयोग और समर्थन देता है। ईश्चम एशिया में अशांति केवल सलिए नहीं है कि ईजरायल लस्तीन को एक अलग देश के प में स्वीकार करने को तैयार हीं। इस अशांति का एक बड़ा गंभीर ईरान भी है, जो ईजरायल

का समूल नाश करने का अपना सनक से ग्रस्त है। ईरान की तरह कतर भी इजरायल विरोधी संगठनों की मदद करता है। ये दोनों देश ऐसा इसलिए भी करते हैं, ताकि खुद को इस्लामी जगत का अगुआ साबित कर सकें। इजरायल और अन्य इस्लामी देशों के बीच दुश्मनी और युद्ध का एक लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन मौजूदा अशांति का मूल कारण एक साल पहले सात अक्टूबर को गाजा आधारित आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल में किया गया बर्बर हमला रहा। इस भीषण हमले में 12 सौ से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। इस हमले के दौरान हमास के आतंकी दो सौ से अधिक इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। हमास ने इन बंधकों को रिहाकर कोई समझौता करने से इन्कार करके गाजा में अपने लोगों को एक तरह से जानबूझकर मरवाने का ही काम किया। इजरायल ने हमास को तबाह करने की कोशिश में गाजा में जा भाषण हमल किए हजारों फलस्तीनी मारे जाए हैं। यह सही है कि इस हमेशा ही ईट का जवाब पढ़ा देता है, लेकिन शायद यह देश ऐसा ही करेगा, जिसे अस्तित्व पर संकट नजर आयदि यह अपेक्षा की जा रही इजरायल संयम बरते और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का शक्ति के बल पर मिटाने वाले छोड़े तो ईरान और अन्य देशों से भी यही अपेक्षित है। इजरायल का नामो निशान की मानसिकता का परित्याकार वास्तव में इसी मानसिकता वाले अमेरिका और कुछ अन्य देशों में इजरायल का साथ नीति पर चलते हैं। चूंकि राष्ट्र सुरक्षा परिषद असहमति अक्षम है, इसलिए पश्चिम में सुलह—समझौते के आसान दिखते। यदि वहां हालात और होते हैं तो इससे विश्व शास्त्रीय वैश्विक अर्थव्यवस्था भी में पड़ेगी, जो यूक्रेन युद्ध के पहले से ही संकट में है।

बायोमेडिकल कपरे के कुप्रबंधन

एक आदमा का कचरा दूसरा आदमा का लेख खाजाना है, बायोमाइकल कचरे के मामले में संचयन एसाईटी ही है। औसतन, एक अस्पताल हर दिन प्रति विस्तर सर्जिकल दस्ताने, सलाइन बोतलें, प्ट ट्यूब, सीरिंज आदि के रूप में लगभग 100 ग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। अगर इसे ठीक से नष्ट किया जाए, तो इससे अस्पताल को रीसाइकिलर से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 रुपये मिलते हैं। लेकिन जब अवैध रूप से बेचा जाता है और दोबारा पैक किया जाता है, तो प्रत्येक वस्तु 75–100 रुपये की कुल कीमत के साथ बाजार में वापस आ जाती है – लाभ में लगभग 20 गुना वृद्धि। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में बायोमेडिकल कचरे के कथित दुरुपयोग और इसके अनुचित निपटान केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दायरे में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, 2014 में पश्चिम बंगाल में 1.03 लाख अस्पताल के बिस्तर थे, जिनसे प्रतिदिन 42.2 लाख टन कचरा निकलता था, जिसमें से केवल 22.7 लाख टन का ही उपचार किया जाता था। 2023 में, जबकि बिस्तरों की संख्या बढ़कर 1.68 लाख हो गई थी – 63: की वृद्धि – उत्पन्न कचरे में 2: से भी कम की वृद्धि हुई और यह सब स्पष्ट रूप से उपचारित किया गया था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2017 में उपचारित बायोमेडिकल कचरे की मात्रा उत्पन्न होने वाले कचरे से अधिक थी। आंकड़ों में स्पष्ट अंतर है।

दुरुपयोग ही एकमात्र समस्या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि ज्ञात्पन्न होने वाले

दुरुपयोग हा एकमात्र समस्या नही ह। स्वास्थ्य विभाग के आकड़ बतात ह कि उत्पन्न हानि वाल बायोमेडिकल कचरे का एक हिस्सा भी गलती से साधारण कचरे के साथ फेंक दिया जाता है। बायोमेडिकल कचरे के कुप्रबंधन में पश्चिम बंगाल अकेला नहीं है। 2023 में, कर्नाटक अपने लगभग 40: बायोमेडिकल कचरे को अनुपचारित छोड़ रहा था।

भारत में बायोमेडिकल कचरे के निपटान को विनियमित करने वाले कानूनों की कोई कमी नहीं है। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 इसका एक उदाहरण है। लेकिन हमेशा की तरह, कार्यान्वयन में ढिलाई बरती जाती है। परिचम बंगाल में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और स्वास्थ्य वेभाग के अधिकारियों जैसे नियामक निकाय अक्सर दूसरी तरफ देखते हैं जबकि अस्पताल – सार्वजनिक और निजी – बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान कानूनों का उल्लंघन करते हैं।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि बायोमेडिकल अपशिष्ट – कोविड-19 महामारी के बाद से इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है – गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरे पैदा करता है। बायोमेडिकल कचरे को रंग-कोडिंग और अलग-अलग करने, अस्पताल के कर्मचारियों को इसे निपटाने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण देने और उत्पन्न और निपटाए गए कचरे की मात्रा का सख्त रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं को इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार का इंतजार, अक्षम हो चुकी हैं संस्थाएं

शिवकांत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भविष्य शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा, शुद्धिनिया एक बवंडर में फंसी है। हम ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक समाधान चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था, एसुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं आज पूरी तरह अप्रासंगिक, अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। इनमें सुधार किए बिना वैश्विक चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, हताश होने के बजाय हमें एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को और सक्षम, प्रभावी और समावेशी बनाने की जरूरत है। इसीलिए हम सुरक्षा परिषद का सुधार और विस्तार करने का सार्वत्रिक वैश्विक संस्थाओं में सुधार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, सुधार आर प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। मानव की सफलता उसकी संगठित शक्ति में है, जंग के मैदान में नहीं। इन वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार के लिए आम सहमति बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार करने और अफ्रीका को स्थायी सीट देने की मांग रखी। महासचिव गुटेरेस ने माना है कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने पर सहमति हो चुकी है, पर सुधार और विस्तार की प्रक्रिया क्या हो और इसकी शुरुआत कब हो, इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही। लैटिन अमेरिका से ब्राजील ने अपनी समीक्षा देने पर भी

किसी को आपत्ति नहीं है। मसला विश्व की दो तिहाई आबादी और लगभग आधी अर्थव्यवस्था वाले एशिया का है, जिसका प्रतिनिधित्व अकेले चीन के पास है। यूरोप के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तीन सीटें हैं। इसलिए कुछ देशों का सुझाव है कि इन तीन देशों में से कम से कम एक को अपना वीटो अधिकार और सीट छोड़ देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दर्शकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर आम सहमति है, परंतु चीन को वीटो अधिकार

नहीं, खासकर एशिया से जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों, भारत और जापान पर वह अलग-अलग कारणों से सदेह करता है। यह समय की विडंबना है कि भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में आड़े आ रहा है। चीन के अलावा भारत के दूसरे पड़ोसी देश भी चुनाव प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया, सैद्धानिक संस्थाओं और मानवाधिकारों पर उचित-अनुचित सवाल उठाकर स्थायी सदस्यता की राह को कठिन बनाते रहते हैं। अमेरिका भी भारत की खेमेबाजी से परे अवसरानुकूल कूटनीति को लेकर आशंकित रहा है।

राष्ट्र चार्टर के उल्लंघनों को यदि न भी रोक सकें, तो भी कम से कम संयुक्त राष्ट्र के नाम पर इराक पर किए गए हमले जैसी विवादास्पद कार्रवाइयों को तो रोक सकें। यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता और फलस्तीनियों के अस्तित्व की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र की बेचारगी दिखाती है कि उसकी संस्थाएं कितनी अयोग्य और अक्षम हो चुकी हैं। वैश्विक व्यवस्था को बहाल करने के लिए नाम के सुधारों की नहीं, बल्कि कारगर सुधारों की जरूरत है, जो मनमानी को रोक सकें। आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा तय करने और उसकी रोकथाम के लिए वैश्विक रणनीति बनाने की भी जरूरत है, ताकि हमास, लश्कर और अल-

रोकथाम की जा सके। साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष में व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी वैशिक चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन तीनों का जिक्र किया, क्योंकि इनमें असुरक्षा रहने से संचार से लेकर व्यापार तक हर पहलू प्रभावित होता है। इस समय विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कृत्रिम मेधा और जलवायु परिवर्तन। कृत्रिम मेधा से प्रशिक्षित हो रहीं मशीनों का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। इनका सही प्रयोग कायाकल्प कर सकता है तो दुरुपयोग के कल्पनातीत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। साइबर, संचार और जैविक आतंक के क्षेत्रों में इस तकनीक के दुरुपयोग की घातकता परमाणु उत्तिष्ठानों से ज्ञात रही है। उत्तिष्ठा

इसके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक वैशिक रणनीति की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर तो हमारा अस्तित्व ही निर्भर करता है।

इसलिए उस पर ऐसी बहुपक्षीय और बहुकाणीय रणनीति बनाने की जरूरत है, जो कारगर होने के साथ-साथ व्यावहारिक और न्यायसंगत भी हो। भारत इन वैशिक चुनौतियों का सामना करने के लिए वैशिक व्यवस्था में सुधारों की पैरवी और अगुआई तभी कर सकता है, जब वह अपने यहां भी समयोदयित सुधारों में आगे रहने की मिसाल कायम करे। आर्थिक सुधारों की गाड़ी मंथर गति से अटक-अटक कर चल रही है। भूमि, श्रम और न्यायिक सुधारों की बात ही शुरु कर्मी नहीं है।

सक्षम स्पीच हियरिंग एंड आटिज्म के प्रेरणा सेंटर उद्घाटन समारोह सम्पन्न महिलाओं को किया गया पुलिस द्वारा जागरूक

लखनऊ व्यूरो चीफ
लखनऊ। सक्षम स्पीच हियरिंग
ड ऑटिज्म केयर सेंटर विकल्प
ड गोमती नगर लखनऊ का आज
नांक 5-10-2024 को भव्य
द्वाधाटन का मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड दश शासन के पूर्व संयुक्त सचिव
शिव शंकर द्विवेदी द्वारा फीटा
टकर किया गया। इस अवसर पर
कटर श्री द्विवेदी जी ने अपने वक्तव्य
माध्यम से विश्वास किया कि यह
टर एक साथ श्रवण बाधित, अस्थिर
धित और मानसिक रूप से समस्याओं
स्त विशेष बालकों के निदान के
ए मील का पत्थर साबित होगा।
र्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री
तर्दं दुबे जी सहायक पुलिस आयुक्त
तर प्रदेश लखनऊ ने कहा कि
माज में दिव्यांग लोगों के उपचार
लिए यह केंद्र उपयोगी रहेगा।
या समाज में ऐसे लोगों की सेवा
रना ही धर्म है।

वाशस्ट आताथ श्रा भनाप शुक्ला
वक्ता भाजपा उत्तर प्रदेश ने दिव्यांग
कितियों के कल्पणा हेतु केंद्र के
फल संचालन के लिए साधुवाद
या स प्रोफेसर विजय शंकर शर्मा
भाग अध्यक्ष विशेष शिक्षा श्री शकुन्तला
श्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
खनऊ में सभी प्रकार के दिव्यांगों

A group of approximately ten men in formal Indian attire (shirts and dhotis) are gathered for a ceremonial event. They are holding yellow ribbons and ceremonial swords (vishwas). The background features a room decorated with orange marigold garlands (mala) hanging from the ceiling. One man in a red shirt is prominent in the center-left, while others are arranged in a semi-circle behind him. The overall atmosphere suggests a formal inauguration or opening ceremony.

लगभग 41 लाख दिव्यांग व्यक्ति हैं जिसमें 20% लोगों को चलने फिरने में समस्या है तो 19% दिव्यांग सुनने और देखने में समस्या ग्रस्त हैं इसी तरह से 7% श्रवण बाधित और 6% मानसिक रूप से बाधित हैं स ऐसी स्थिति में ऐसे केन्द्र निश्चित रूप से समाज के लिए उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार ज्ञापित करते हुए इस केंद्र के निदेशक डॉ कपिल मुनि दुबे जी आश्वस्त किया है कि श्रवण बाधित वाणी वाधित तथा मानसिक ग्रस्त व अस्थिबाधित लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए स्पीच थेरेपी,ऑक्यूप्रैशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी तथा स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों का निदान कर बेसिक ज्ञान भी सिखाया जाएगा इस अवसर पर सब रजिस्टर श्री अवधेश मिश्रा डॉक्टर सचिन गिरी एम डी न्यूरोलॉजिस्ट राम मनोहर लोहिया लखनऊ, डॉक्टर सुधीर सिंह एम डी गैस्ट्रोलॉजिस्ट ,श्री हर्षित मिश्रा सांख्यिकी अधिकारी, श्री शेर बहादुर एस एच ओ 1090 लखनऊ,श्री नीलम पांडे,संजय उपाध्याय,हिमांशु शुक्ला, रजनीकांत, शुभम चौहान ,अतुल वर्मा,आमिर,संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे।

मुख्य
काश श्रीवास्तव
। जफराबाद थाना क्षेत्र
बैंक नेहरूनगर की शाखा
र को पुलिस ने मिशन
यान के तहत महिलाओं
ओं को जागरूक किया
प्रक्रम में उक्त ब्रांच में
लाओं व छात्राओं को
महिलाओं को दी जाने
योजना की जानकारी
दी गयी। योजनाओं में आपदा काल
में 1090, 1098, 1076, 1930, 181, 112
तथा 108 हेल्पलाइन नम्बरों की
विस्तृत जानकारी दी गयी।
महिलाओं को उनके अन्य अधिकारों
की भी जानकारी दी गई। यह
जानकारी महिला आरक्षी उपासना
सिंह तथा रीमा सिंह ने दिया। इसके
दौरान महिलाओं को शासन द्वारा
महिला अधिकारों की पुस्तिका भी
बांटी गई।

**क्रीय आई०टी०आई० में 10 अक्टूबर
0.00 बजे रोजगार मेला का आयोजन**

मुख्य काश श्रीवास्तव | जिला सेवायोजन अधिकारी प्रकाश पासवान ने अवगत के निदेशक, प्रशिक्षण एवं उत्त०प्र०० एवं जिलाधिकारी के क्रम में राजकीय ई० जौनपुर में 10 अक्टूबर तातः 10.00 बजे रोजगार योजन किया गया है। दो क्षेत्र की 10 कम्पनियों ने भेटाभाग किया जाना है। विक्षित योग्यता हाईस्कूल, ०टी०आई० एवं स्नातक युसीमा 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों को कैम्पस सलेक्शन करेंगी। जिसमें अभ्यर्थी अपने योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए विभिन्न पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति आई०टी०प्र०० बायोडाटा सहित प्रतिभाग करेंगे। एवं सेवायोजन वेब पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की है।

तहसीलदार एवं पुलिस बल के साथ भूमि कछा मुक्तकराये - मंगला



मीन की पेंशन शीघ्र बहाल करायें और उसे ऐसा अपेक्षाएँ कर रखें। दिवस से पूर्व आवश्यक करायें। तभी अलगता से मिला अपीलक

के नये पश्चात् आवदनों का ब्लाक एवं नगरीय निकायों से सत्यापन कराने के उपरान्त स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित करें। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी समस्त संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी निर्माण कार्यों में शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अदिकारियों को निर्देश दिये कि नियमित कार्यालय में बैठकर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को स्वयं देखें और उनका ससमय निस्तारण करायें और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल, शासन, सम्पूर्ण समाधान एवं थाना समाधान दिवस से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण भी ससमय एवं गुणवत्ता पूर्ण करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में आयी शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये आज प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अगले सम्पूर्ण समाधान

राजकीय आई०टी०आई० में 10 अक्टूबर
प्रातः 10.00 बजे रोजगार मेला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
जौनपुर। जिला सेवायोजन अधि
कारी जय प्रकाश पासवान ने अवगत
कराया है कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं
सेवायोजन उ०प्र०० एवं जिलाधिकारी
के निर्देश के क्रम में राजकीय
आई०टी०आई० जौनपुर में 10 अक्टूबर
2024 को प्रातः 10.00 बजे रोजगार
मेला का आयोजन किया गया है।
जेसमें निजी क्षेत्र की 10 कम्पनियों
के द्वारा प्रतिभाग किया जाना है।
जेसकी शैक्षित योग्यता हाईस्कूल,
इंटर, आई०टी०आई० एवं स्नातक
उत्तीर्ण आयुसीमा 18 से 35 वर्ष के

अभ्यर्थियों को कैम्पस सलेक्शन
करेंगी। जिसमें अभ्यर्थी अपने
योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए
विभिन्न पदों पर साक्षात्कार के माध्यम
से रोजगार प्राप्त करें। जिला
सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि
रोजगार मेला में सम्मिलित होने के
लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त
शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति आई०टी०
प्रूफ बायोडाटा सहित प्रतिभाग करेंगे
एवं सेवायोजन वेब पोर्टल rojgaar
sangam .up .gov.in के माध्यम
से पंजीकरण कर अभ्यर्थियों को
अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग
करने की अपील की है।

दिन दहाड़ युवक का हत्या क्षेत्र में सनसनी

मुलांगुनी पातापाला दहरा थाने
भ्रंतर्गत तिवारीपुर कुटीवा गांव में
अठारह वर्षीय युवक की धारदार
हथियार से हत्या। दिनदहाड़े हुई
धारदात से फैली सनसनी। मृतक
गोलू वर्मा पुत्र शिवलाल वर्मा नाम से
युवक की पहचान। लोहारन का पुरवा
पीपर पुर निवासी बताए जा रहे
हथार। नाय पाला ने कातापाला दहरा
पुलिस को दी सूचना, इंस्पेक्टर सत्येन्द्र
कुमार सिंह मयफोर्स घटना स्थल
पर मौजूद।

एसपी सोमेन वर्मा बोले, आपसी
विवाद में हुई वारदात। जांच पड़ताल
कर जल्द किया जाएगा मामले का
खुलासा।

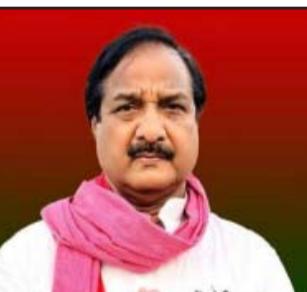
सुल्तानपुर। शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पहल पर जीआईसी ग्राउंड को खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के लिए सुरक्षित केया जा रहा है। 27 लाख 50 हजार के मद से स्थाई बैरिकेडिंग ग्राउंड्री वॉल निर्माण कार्य के लिए जेला विद्यालय निरीक्षक की मौजदगी

शहर विधायक के सहयोगी राजेश कुमार पांडेय की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई। जीआईसी ग्राउंड पर अनावश्यक अंतिक्रमण की समस्या से निजात मिल जाएगी। खेलकूद के साथ अन्य प्रशासनिक कार्यक्रम भी यहां आयोजित किए जाएंगे। पर्व बीएसए दीपिका चतुर्वेदी

जीआईसी प्राचार्य मनोज कुमार मेश्रा द्वारा शुक्रवार को भूमि पूजन केर्या गया। अवस्थापना मद से पीडब्ल्यूडी काई निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभालेगी। अक्तूबर को चिन्ह विदालय

लैंड रहर पवित्रपक्ष का धन्यवाद
ज्ञापित किया है। इस मौके पर दिनकर
प्रताप सिंह, पवन कुमार, अरुण तिवारी
आदि लोग मौजूद रहे।

सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया



से प्रक्रिया जारी करने के बावजूद न्यायालय में उपरिथित न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में मृतक का शव पुलिस की देख-रेख में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था। आरोपी रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शव को पटना चौराहे पर सड़क के बीचोबीच रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था। इससे आवागमन बाधित हो गया। थानाध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनके हमराहियों ने जाम खुलवाने का प्रयास किया गया तो आरोपी और उनके सहयोगी पुलिस के साथ गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी।

रक्तदान संस्थान के द्वारा रक्तदाताओं ने
शेखुर मिश्र के लेतत्व में किया उत्कृष्ट

मछलीशहर। क्षेत्र के रीठी निवासी
एक गर्भवती महिला डॅगू पीड़ित हो
ई, जिसका उपचार शिवाय वित्तनिक
जौनपुर में चल रहा था इसी दौरान
महिला की डिलीवरी भी होनी थी,
आकस्मिक डॅगू पीड़ित होने के कारण
महिला का प्लेटलेट्स 13000 हो
या था जिससे महिला की स्थिति
माजुक बनी हुई थी, इसकी खबर
रक्तदान संस्थान को लगी, रक्तदान
संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता पंडित
नवेहंश दुबे ने अपने सहयोगी कार्यकर्ता
पंडित शेखर मिश्रा के माध्यम से श्री

राम को जन्म भूमि में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अयोध्या और उपमुख्यमत्रा बृजश पाठक और अयोध्या कमिशनर गौरव दयाल,

जिला कृषि अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अयोध्या। भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम-प्रणाम और नैनौ के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को जिला कुपि अधिकारी अयोध्या ओम प्रकाश तक भेजकर उसके उद्देश्य के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यूरिया के वैकल्पिक उर्वरक नैनौ या श्री ओम प्रकाश मिश्र जी ने बताया कि यह प्रचार वाहन आज 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हर



यूरिया और जैविक खाद के फसल में उपयोग करने से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा और परिवहन व्यय कम होगा और कम लागत में उत्पादन अधिक होगा और किसान विकास खंड में जाकर किसान भाइयो को जागरूक करेगा इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र जी के साथ हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन

